

प्रेषक,

एम०एच० खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक- 01 सितम्बर, 2013
अ.2.48

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार में दो सीवरेज परियोजनाओं की वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: भा०स० 243/IV(2)-श०वि०-11-29(एन०यू०आर० एम०)/09, दिनांक 24.12.2011 एवं संख्या: 463/IV(2)-श०वि०-11-29(एन०यू०आर० एम०)/09, दिनांक 30.03.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से भारत सरकार द्वारा हरिद्वार में स्वीकृत दो सीवरेज परियोजना यथा जोन-D एवं जोन E-1 हरिद्वार तथा जोन-C2 हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए क्रमशः ₹861.59 लाख एवं ₹516.95 लाख इस प्रकार कुल ₹1378.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०- 59(1)/PF-1/2013-603, दिनांक 22.08.2013 द्वारा जोन D एवं जोन E-1 हेतु ₹233.47 लाख तथा जोन C-2 हेतु ₹122.91 लाख, अर्थात् कुल ₹356.38 लाख सी०एस०एम०सी० की 124वीं बैठक में अवमुक्त किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में हरिद्वार शहर की जोन D एवं जोन E-1 सीवरेज योजना हेतु ₹233.47 लाख केन्द्रांश व ₹93.99 लाख राज्यांश अर्थात् कुल ₹327.46 लाख तथा जोन C-2 योजना हेतु ₹122.91 लाख केन्द्रांश व ₹49.16 लाख अर्थात् कुल ₹172.07 लाख (समग्र धनराशि ₹499.53 लाख) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि ₹499.53 लाख (चार करोड़ निनानवे लाख तिरपेन हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इसे वह पी०एल०ए० खाते में रखेंगे।
- (ii) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- (iii) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (iv) जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- (v) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (vi) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (vii) निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15-12-2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
- (viii) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- (vii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों एवं उक्त सभी के विषय में समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- (viii) आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ix) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (x) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
- (xi) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
- (xii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2014 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय के अनुदान सं0-13, लेखाशीर्षक "4217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे ₹394.75 लाख, अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद के नामे ₹89.81 लाख तथा अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में ₹14.97 लाख धनराशि के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-446/XXVII(2)/2011, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28-03-2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-S.131.0.13.0.0.32., S.131.0.3.0.0.0.33. एवं S.131.0.3.1.0.0.34 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

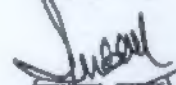
(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

सं0 1349 (1)/IV(2)-शा0वि0-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
13. बजट सजेकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(सुमीत चन्द्र)
उप सचिव।